

प्रेषक,

डा० राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3,

देहरादून: दिनांक 06 अगस्त 2009

विषय:- वित्तीय वर्ष 2009-10 में माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु
आय-व्ययक की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-515/XXVII(I)/2009, दिनांक 28 जुलाई 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शालम्नक में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान संख्या-11, 30 व 31 के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए आयोजनागत पक्ष की बचनबद्ध मदों में रु० 1410735 हजार एवं आयोजनेत्तर पक्ष की बचनबद्ध मदों में रु० 12046863 हजार, इस प्रकार कुल रु० 13457598 (रुपये तेरह अरब, पैंतालीस करोड़ पछहत्तर लाख अठानवे हजार मात्र) की धनराशि, को इस प्रतिबन्ध के साथ आपके निर्वर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा बचनबद्ध मदों में यथा वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, मजदूरी, विद्युत देय, जलकर, किराया, पेंशन, औषधि, भोजन व्यय, टेलीफोन आदि आवश्यक व्ययों का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त मदों से भिन्न मदों एवं समस्त चालू निर्माण कार्य, नये निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय तथा त्राहन क्रय की स्वीकृतियों के प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

2- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा तक किये जाने का दायित्व आपका होगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा:-

- 1- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- 2- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
- 3- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
- 4- आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय।
- 5- मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से धालन किया जायेगा।
- 6- व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कौषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

अर्प

- 7- स्वीकृत धनराशि की जिलावार फाँट सम्बन्धित जिलों एवं शासन को तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
 - 8- वित्तीय वर्ष 2009-10 में इसके पूर्ववर्ती वर्षों के एरियर भुगतान यदि कोई हों, के विवरण की सूचना अलग से रखी जाय।
 - 9- अप्रैल, 2009 से नये पदों के भरे जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय के सापेक्ष श्रेणीवार पदों (समूह "क" "ख" "ग" व "घ") की सूचना रखी जाय।
 - 10- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुवल, वित्तीय हस्तपुरितका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
 - 11- निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/ पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों की लक्ष्य के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण अनिवार्य रूप से किया जाय।
 - 12- किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर शासन की सहमति के किसी भी प्रकार से पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।
 - 13- बजट मैनुवल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जानी वाली सूचना समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
 - 14- वाह्य सहायतित परियोजनाओं, अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए ट्राइबल सबप्लान के अन्तर्गत आवंटित परिव्यय के सापेक्ष बजट प्राविधान को अन्य योजना हेतु व्यावर्तित न किया जाय।
 - 15- किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पाँच भाग-1 (लेखा नियम) आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों, आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 - 16- यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय-व्ययक 2009-10 में बजट प्राविधान लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय-व्यय के प्राविधान की सीमा तक ही व्यय की जायेगी।
- 3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा" -02-माध्यमिक शिक्षा एवं 2205-कक्षा एवं संस्कृति-105-सार्वजनिक पुस्तकालय "4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-202-माध्यमिक शिक्षा के अधीन सलग्नक में उल्लिखित सम्बन्धित ब्योरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त विभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-515/XXVII (I)/2009, दिनांक 28 जुलाई, 2009 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।
- संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(**डॉ० राकेश कुमार**)
सचिव ।

13

(3)

संख्या: 1183 (1) / XXIV-3/09/02(34)/2009-T.C. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- मन्त्रालयाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मः मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
- 3- निजी सचिव, मः शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- उत्तर राजकीय नियोक्ता एवं सहायक निदेशालय, सचिवालय।
- 6- उत्तराखण्ड मन्त्रालय, मन्त्रालय नदी, उत्तराखण्ड मन्त्रालय, मन्त्रालय।
- 7- मन्त्रालय अपर शिक्षा निदेशक, मन्त्रालय नदी, उत्तराखण्ड मन्त्रालय, मन्त्रालय।
- 8- रामरतन जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9- रामरतन जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 10- उत्तर शिक्षा निदेशक एस0सी0इ0आर0टी0 नरेंद्र नगर टिहरी।
- 11- सचिव, उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल।
- 12- रामरतन जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 13- प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल घांझावाल नैनीताल।
- 14- वित्त विभाग/नियोजन प्रयोक्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 15- कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
- 16- एन0आइ0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 17- अनुभाग अधिकारी, शिक्षा अनुभाग-2 4 एवं 5 उत्तराखण्ड शासन।
- 18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

9

(पी0एल0शाह)

उप सचिव।